



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 2009/भाद्र 20, 1931

No. 524]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2009/BHADRA 20, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2009

सं. 100/2009-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 666(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट माल को निम्न प्रकार शुल्क से मुक्त करती है :—

- (i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय उतनी सीमा-शुल्क से, जो मूल्य के तीन प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है;
- (ii) उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से, जब आयातक द्वारा विशेष रूप से दावा किया गया हो।

2. इस अधिसूचना के तहत छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगी, अर्थात् :—

- (1) यह कि आयातित माल, विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 के निबंधनों के अनुसार निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक (एतदपश्चात् डी जी एफ टी के रूप में उल्लिखित), वाणिज्य विभाग (एतदपश्चात् डी ओ सी के रूप में उल्लिखित) अथवा निर्यात उत्कृष्टता वाले शहरों में राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम (एतदपश्चात् टी ई ई के रूप में उल्लिखित) द्वारा सामान्य सेवा प्रदाता (एतदपश्चात् सी एस पी के रूप में उल्लिखित) को जारी की गई किसी विधिमाम्य अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आता है, जिसके द्वारा तीन प्रतिशत शुल्क की दर से माल का आयात अनुज्ञात किया गया है और उक्त प्राधिकार निकासी के समय उपयुक्त सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा विकलन के लिए प्रस्तुत की जानी है :

परन्तु उक्त सारणी की क्रम संख्या 4 में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए प्राधिकार की विधिमाम्य अवधि वह अवधि मानी जाएगी जो संपूर्ण निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिए अनुज्ञात की गई हो;

- (2) यह कि स्कीम के अंतर्गत जारी प्राधिकार में उक्त कारखानागत माल के प्रयोक्ताओं का ब्यौरा तथा प्रत्येक प्रयोक्ता द्वारा पूरी की जाने वाली निर्यात बाध्यता (एतदपश्चात् ई ओ के रूप में उल्लिखित) की राशि का उल्लेख होगा।
- (3) यह कि निर्यात की बाध्यताएं पूरी होने तक आयातित माल को बिक्री/पट्टे या किसी और तरीके से निस्तारित या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

(4) यह कि सामान्य सेवा प्रदाता और विशिष्ट प्रयोक्ताओं में से प्रत्येक लाइसेंस अथवा प्राधिकार जारी होने से आठ वर्षों की अवधि के अंदर सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रपत्र पर और ऐसी धनराशि का बांड भरेगा और प्राधिकार में निर्धारित निर्यात बाध्यता के दृष्टिकोण से छोड़े गए शुल्क के समतुल्य बैंक गारंटी देगा जो उसे पोत पर्यंत निःशुल्क (एफ ओ बी) आधार पर प्राधिकार में विनिर्दिष्ट आयातित माल पर बचाए गए शुल्क के 8 गुने के बराबर या ऐसी अधिक धनराशि जो हैंडबुक क्रियाविधि खंड-1 के पैरा 5.10 के निबंधनों के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा नियत किया जाए, निर्यात बाध्यता पूरी करने के लिए निम्नलिखित अनुपात में बाध्य करें, नामशः-

क्र. सं.	अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से अवधि	कुल निर्यात बाध्यता का अनुपात
1	2	3
1	पहले से छठे वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत
2	सात से आठ वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत

परन्तु जहां बचाया गया शुल्क 100 करोड़ रुपये से कम न हो अथवा जहां कृषि निर्यात जोन में इकाइयों को प्राधिकार जारी किया जाता है, जैसा कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाता है, वहां निर्यात बाध्यता प्राधिकार जारी किए जाने की तारीख से बारह वर्षों की अवधि के भीतर निम्न अनुपातों में पूरी की जाएगी, अर्थातः-

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से अवधि	कुल निर्यात बाध्यता का अनुपात
1	2	3
1	एक से 10 वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत
2	11 से 12 वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत

परन्तु यह कि जहां कोई रुग्ण इकाई औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अधिसूचित है अथवा जहां रुग्ण इकाई के संबंध में इसके पुनर्संजीवन के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा कोई पुनर्वास स्कीम घोषित की जाती है, वहां निर्यात बाध्यता संचालक एजेंसी द्वारा तैयार और बी आई एफ आर/राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकरण अथवा क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमत्य अवधि के अंतर्गत पूरी की जाएगी। जिन मामलों में पुनर्वास पैकेज में समयावधि विनिर्दिष्ट नहीं है उनमें निर्यात बाध्यता लाइसेंसिंग प्राधिकरण अथवा क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमत्य समयावधि के अंतर्गत पूरी की जाएगी जो बारह वर्षों से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते कि जहां पूंजीगत माल का आयात कृषि इकाइयों और छोटे और कुटीर उद्योग क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किया जाता है, वहां पर निर्यात बाध्यता आयातित माल पर बचाए गए शुल्क के छह गुने के बराबर जैसा कि प्राधिकार में विनिर्दिष्ट है, निश्चित की जाएगी, या ऐसी उच्चतर राशि के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार को जारी किए जाने की तारीख से बारह वर्ष के भीतर निश्चित की जाएगी।

यह भी शर्त है कि जहां पूंजीगत माल का विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.8 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार प्रौद्योगिकीय उन्नति के लिए आयात किया जाता है या विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.2 में परिभाषित लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा, जैसा भी मामला हो, आयात किया जाता है, वहां निर्यात बाध्यता प्राधिकार में यथा विनिर्दिष्ट आयातित माल पर बचाए गए शुल्क से छः गुने के बराबर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित अधिक धनराशि की निर्यात बाध्यता प्राधिकार जारी होने के आठ वर्ष के भीतर निश्चित की जाएगी। आगे शर्त है कि एस एस आई इकाइयों के मामले में इस योजना के अंतर्गत ऐसे आयातित पूंजीगत माल की लैंडेंड सी आई एफ मूल्य 50 लाख रु. से अधिक नहीं होगा और ऐसे आयात के बाद संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश एस एस आई सीमा से अधिक नहीं होगा।

यह भी प्रावधान किया गया कि वर्तमान संयंत्र और मशीनरी (ई पी सी जी के अंतर्गत अथवा अन्य रूप से पूर्व में आयातित) के लिए पूर्यो (पुनः मरम्मत/ तैयार किए गए पूर्यो सहित), ढांचों, रंगों, जुगतों, जुड़नारों, यंत्रों, प्रारम्भिक लाइनिंग के लिए प्रतिरक्षितों और प्रारम्भिक प्रभार के लिए उत्प्रेरकों को ई पी सी जी स्कीम के अंतर्गत इस शर्त के अधीन आयातित करने की अनुमति दी जाएगी कि ऊपर विहित सामान्य निर्यात बाध्यता के 50% के समतुल्य निर्यात बाध्यता प्राधिकार जारी होने की तिथि से 8 वर्षों में पूरी की जाएगी बशर्ते कि उक्त पूर्यो, आदि के आयात का सी आई एफ मूल्य ई पी सी जी प्राधिकार के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी के सी आई एफ मूल्य के 10% तक सीमित होगा अथवा ई पी सी जी स्कीम के अलावा अन्य रूप से पूर्व में आयातित संयंत्र और मशीनरी के बुक वैल्यू के 10% जैसा मामला हो, तक सीमित होगा।

परन्तु किसी विशिष्ट ब्लॉक वर्ष की निर्यात बाध्यता को पूर्ववर्ती ब्लॉक में किए गए अधिक निर्यातों द्वारा मंजूर किया जा सकेगा;

(5) यह कि यदि आयातकर्ता सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के संबंध में छूट का दावा नहीं करता है, तो उसे निर्यात बाध्यता के परिगणन के संबंध में बचाई गई शुल्क राशि के संगणन के प्रयोजनार्थ उक्त सीमा शुल्क से छूट प्राप्त करने संबंधी लाभ उठाने वाला नहीं समझा जाएगा बशर्ते अतिरिक्त शुल्क अदा करने का सेनवैट क्रेडिट न लिया गया हो;

(6) यह कि प्राधिकार धारी एवं अन्य विशिष्ट प्रयोक्ता अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से प्रत्येक ब्लॉक की समाप्ति से 30 दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या उप सीमा शुल्क आयुक्त अनुज्ञात करें, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या उप सीमा शुल्क आयुक्त को समाधानप्रद रूप में पूरी की गई निर्यात बाध्यता का परिणाम दर्शित करने से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करता है और जहां किसी विशिष्ट ब्लॉक की निर्यात बाध्यता पूर्ववर्ती शर्त के निबंधनों के अनुसार पूरी नहीं की गई है, वहां आयातकर्ता, उक्त ब्लॉक की समाप्ति से तीन मास के भीतर उतनी रकम का, जो यदि इसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती तो, माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उस भाग के बराबर का जिसका वही अनुपात है जो निर्यात बाध्यता को पूरा न किया गए भाग का कुल निर्यात बाध्यता से है, माल की

निकासी की तारीख से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित संदाय करेगा;

(7) जहां प्राधिकार धारी शर्त (4) में विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता की अवधि की आधी अवधि में शर्त (4) में विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता का 75% या उससे अधिक (औसत निर्यात बाध्यता के 100% के अतिरिक्त) पूरी करता है, उसकी शेष निर्यात बाध्यता माफ कर दी जाएगी और यह माना जाएगा कि उसने सारी निर्यात बाध्यताएं पूरी कर दी हैं।

(8) यह कि आयातित, समंजित या विनिर्मित पूंजी माल आयातकर्ता के कारखाने या परिसर में संस्थापित किए जाते हैं और अधिकारिता वाले यथा-स्थिति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त से आयातकर्ता के कारखाने या परिसरों में पूंजी माल के संस्थापन और उपयोग की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण-पत्र आयात पूरा होने की तारीख से छह मास से भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उक्त सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अनुज्ञात करें, यथास्थिति प्रस्तुत किया जाता है:-

बशर्ते पुर्जों के आयात के मामले में, स्थापना प्रमाणपत्र आयात की तारीख से तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

आगे शर्त यह है कि यदि प्राधिकार धारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पंजीकृत नहीं है या वह कोई सेवा प्रदान करने वाला है, जैसा मामला हो, तो वह किसी स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा जारी संस्थापन और प्रयोग का उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है;

बशर्ते कृषि निर्यात जोन में स्थित एगो इकाईयों के लिए सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्राधिकारिक उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सहायक उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को सूचित करते हुए कृषि निर्यात जोन के अंदर पूंजीगत माल को ले जा सकता है, यथास्थिति इस शर्त के अधीन कि ऐसी गतिविधियों का आयातक सही रिकार्ड रखेगा।

(9) यह कि आयात और निर्यात समुद्री बन्दरगाह-बेदी (रोजी-जामनगर सहित), चेन्नई, कोचीन, दहेज, धरमतर, हल्दिया (कोलकाता बन्दरगाह का हल्दिया डॉक काम्पलेक्स) काकीनाडा, कांडला, कोलकाता, कृष्णापटनम, मगडाल्ला, मंगलौर, मारमगोवा, मुलद्वारका, मुम्बई, मुन्धरा, नागापट्टिनम, न्हावा शेवा, ओखा, पारादीप, पिपाव, पोरबंदर, सिक्का, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम तथा वडिनार के माध्यम से अथवा अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोचीन, कोयम्बतूर, डाबोलिम (गोवा), दिल्ली, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ (अमौसी), मुम्बई, नागपुर, राजासांसी (अमृतसर), श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम तथा वाराणसी स्थित किसी विमानपत्तन के जरिए अथवा आगरा, अहमदाबाद, अनापार्थी (आंध्रप्रदेश), बाबरपुर, बंगलौर, भदोही, भटिन्डा, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, भुसावल, छेहाड़ता (अमृतसर), कोयम्बतूर, दादरी, डाप्पर (डेरा बस्सी), दौलताबाद (वंजारवाड़ी तथा मालीवाड़ा), दिल्ली, डिगही (पुणे), दुर्गापुर (निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क), फरीदाबाद, गरही हरसारू, गौहाटी, गुंटूर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर, करूर, कोटा, कुंडली, लोनी (जिला गाजियाबाद), लुधियाना, मदुरै, मलांपुर, मन्डीदीप (जिला रायसेन), मिराज, मुरादाबाद, नागपुर, नासिक, पिम्परी (पुणे), पीतमपुर (इन्दौर), पांडिचेरी, रायपुर, रेवाड़ी, रूद्रपुर (नैनीताल), सलेम, सिंगनालूर, सूरत, सूरजपुर,

तिरुपुर, तूतीकोरिन, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, वालुज (औरंगाबाद) स्थित किसी इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से अथवा अगरतला, अमृतसर रेल कार्गो, अटारी रोड, चांगराबान्धा, डावकी, घोजाडंगा, हिल्ली, जोगबानी, महादीपुर, नेपालगंज रोड, नौतनवा (सोनौअली), पेटरापोल, राणाघाट, रक्सौल, सिंघाबाद तथा सुतारखंडी भू-सीमा कस्टम स्टेन के जरिए अथवा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से किए जाते हैं।

यह प्रावधान है कि सीमा शुल्क आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष आदेश द्वारा अथवा सार्वजनिक नोटिस द्वारा और उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी अन्य समुद्री बंदरगाह, विमानपत्तन, इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा लैंड कस्टम स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

(10) उपर्युक्त शर्त (6) में कुछ भी अंतर्विष्ट हो, जहाँ लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा क्षेत्रीय प्राधिकारी किसी भी ब्लॉक के लिए ब्लॉक क्रम में अवधि बढ़ाने अथवा दो वर्षों की अवधि तक निर्यात देयता को पूरा करने की कुल अवधि अथवा निर्यात देयता में कमी को नियमित करने के लिए अधिकतम ऐसी निर्यात देयता के पाँच प्रतिशत तक, अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता है वहाँ निर्यात देयता की उक्त ब्लॉक क्रम में अवधि अथवा कुल अवधि को सीमा शुल्क के उपायुक्त अथवा सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा मामला हो, द्वारा बढ़ाया/माफ किया जा सकता है:

यह प्रावधान है कि शर्त (4) के दूसरे परन्तुक में उल्लिखित बीमार इकाईयों के संबंध में निर्यात देयता की कुल अवधि को बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

यह भी प्रावधान है कि यदि प्राधिकार धारी निर्यात देयता के पूरा नहीं किए गए अंश पर पचास प्रतिशत अंतर शुल्क का भुगतान करता है और इसके लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों को पूरा करने पर सहमत होता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यात देयता की कुल अवधि को दो और वर्षों की अवधि तक बढ़ा सकता है।

यह भी प्रावधान है कि निर्यात बाध्यता अवधि 8 वर्षों अथवा 12 वर्षों, जैसा मामला हो, की मूल निर्यात बाध्यता अवधि सहित 12 वर्षों से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

3. जहाँ उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट माल दोषपूर्ण अथवा इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त पाये जाते हैं तो उक्त माल को उनके आयात पर शुल्क के भुगतान की तिथि से तीन वर्षों के अंदर विदेशी आपूर्तिकर्ता को वापस पुनर्निर्यात किया जा सकता है।

यह प्रावधान है कि पुनर्निर्यात के समय सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसा मामला हो, की संतुष्टि के लिए माल की आयात किए गए माल के रूप में पहचान की जाती है।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए-

(1) 'कारखानागत माल' का वही अर्थ है जो विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.12 में दिया गया है।

3229 GI/09-2

(2) सामान्य सेवा प्रदाता (सी एस पी) का अर्थ है ऐसा सेवा प्रदाता जो डी जी एफ टी, वाणिज्य विभाग अथवा निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर में राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम द्वारा सामान्य सेवा प्रदाता के रूप में नामित अथवा अधिप्रमाणित हो ।

(3) 'निर्यात देयता'-

(1) का अर्थ है सामान्य सेवा प्रदाता एवं विशिष्ट प्रयोक्ताओं में से प्रत्येक पर भारत से बाहर उत्पादित/उत्पादन के लिए सक्षम अथवा इस अधिसूचना के दृष्टिकोण से आयातित कारखानागत माल के उपयोग द्वारा दी गई सेवा पर देयता। निर्यात देयता बढ़ाई गई अवधि यदि कोई हो, सहित कुल निर्यात देयता अवधि के अंतर्गत उन्हीं उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में आयातक द्वारा प्राप्त निर्यात के औसत स्तर के अलावा होगी। ऐसा औसत उन्हीं उत्पादों के लिए विगत 3 वर्षों में निर्यात निष्पादन का गणितीय औसत होगा ।

यह प्रावधान है कि निर्यात देयता के 50% को आयातक अथवा ई पी सी जी प्राधिकार वाले ग्रुप कम्पनी/प्रबंधित होटल द्वारा उत्पादित अन्य माल अथवा प्रदान की गई सेवा के निर्यात द्वारा भी पूरा किया जा सकता है, परन्तु इस शर्त के अधीन कि ऐसे मामलों में लगाई गई अतिरिक्त निर्यात देयता पिछले तीन वर्षों में आयातक अथवा उसके ग्रुप कम्पनी/प्रबंधित होटल द्वारा मूल और वैकल्पिक उत्पाद/सेवा के लिए प्राप्त औसत निर्यात के अलावा होगी ।

यह भी प्रावधान है कि हस्तशिल्प, हैंडलूम, झोपड़ी, छोटे क्षेत्र, कृषि, पशु पालन, पुष्पकृषि, बागबानी, मत्स्यपालन, द्राक्ष-कृषि, मुर्गी पालन और रेशम-उत्पादन से संबंधित माल के निर्यात के मामले में आयातक द्वारा निर्यात का औसत स्तर बनाए रखना अपेक्षित नहीं होगा ।

यह भी प्रावधान किया गया कि एकवाकल्चर (मतस्य पालन सहित) से संबंधित माल के निर्यात के मामले में आयातक के लिए निर्यात का औसत स्तर बनाए रखना अपेक्षित नहीं होगा बशर्ते कि फिशिंग टूटलर्स, बोट, शिप एवं अन्य ऐसी मदों को छोड़कर माल के लिए ई पी सी जी प्राधिकार प्राप्त कर लिया गया हो ।

यह भी प्रावधान है कि इस अधिसूचना के अंतर्गत आयातित औजारों को छोड़कर माल को उपर्युक्त क्षेत्रों द्वारा आयात की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिए अंतरित करने की अनुमति नहीं होगी, उन मामलों में भी नहीं जहाँ निर्यात देयता पूरी कर ली गई हो। तथापि, कारखानागत माल को निर्यात देयता पूरी करने के बाद परन्तु आयात की तिथि से पाँच वर्षों के अंदर क्षेत्रीय प्राधिकारी और क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को सूचना देते हुए ग्रुप कम्पनियों के बीच अंतरित करने की अनुमति होगी ।

यह भी प्रावधान है कि पुराने यू एस एस आर अथवा दिनांक 31.3.08 तक डी जी एफ टी द्वारा अधिसूचित देशों को किए गए निर्यात को निर्यात के औसत स्तर निर्धारित करने के लिए गिना नहीं जाएगा ।

यह भी प्रावधान है कि केवल ऐसे शिपिंग बिलों के लिए निर्यात को निर्यात देयता को पूरा करने के लिए गिना जाएगा जिन पर ई पी सी जी प्राधिकार सं. और तिथि का उल्लेख होगा ।

यह भी प्रावधान है कि इस अधिसूचना के अंतर्गत जारी प्राधिकार के लिए परिकल्पित निर्यात को अन्य ई पी सी जी प्राधिकारों के लिए विशिष्ट निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने में नहीं गिना जाएगा।

(2) को वास्तविक निर्यात के जरिए पूरा किया जाएगा और निर्यात प्राप्ति को आसानी से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल किया जाएगा। तथापि निम्नलिखित संवर्गों की आपूर्तियों को निर्यात देयता पूरी करने के लिए गिना जाएगा:

(क) सम निर्यात नामतः

(i) अग्रिम प्राधिकार/वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार/ शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डी एफ आई ए) के संबंध में माल की आपूर्ति;

(ii) ई ओ यू अथवा एस टी पी अथवा ई एच टी पी अथवा बी टी पी को माल की आपूर्ति;

(iii) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (आई सी बी) के अंतर्गत अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/कोषों द्वारा उन एजेंसियों/कोषों की प्रक्रियाओं के अनुसार वित्त पोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति, वहाँ विधिक करारों में सीमा शुल्क को शामिल किए बिना निविदा मूल्यांकन का प्रावधान है; आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आई सी बी के अंतर्गत अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/कोषों द्वारा उन एजेंसियों/कोषों की प्रक्रियाओं के अनुसार वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए माल और उपस्करों (प्रमुख ठेकों की एकमात्र जिम्मेदारी) की आपूर्ति तथा उन्हें लगाना जहां बोलियाँ विदेश में उत्पादित माल के लिए डेलीवरी ड्यूटी पेड़ (डी डी पी) कीमतों के आधार पर आमंत्रित कर मूल्यांकन किया गया जाता हो;

(iv) किसी भी ऐसी परियोजना अथवा उद्देश्य के लिए माल की आपूर्ति जिनके संबंध में वित्त मंत्रालय अधिसूचना द्वारा शून्य सीमा शुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति प्रदान करता है और आपूर्ति आई सी बी प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है;

(v) आई सी बी प्रक्रिया के अंतर्गत उपर्युक्त (iv) में शामिल नहीं की गई उर्जा परियोजनाओं और रिफाईनरियों को माल की आपूर्ति;

(vi) आई सी बी के प्रतिकूल प्रतियोगी बोलियों के माध्यम से न्यूक्लियर उर्जा परियोजनाओं को माल की आपूर्ति;

(ख) घरेलू टेरिफ क्षेत्र को आई टी ए-1 मर्चें की आपूर्ति बशर्ते कि सरल विदेशी विनिमय वाली मुद्रा में वसूली हो;

(ग) आसानी से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त रायल्टी भुगतान एवं आर एंड डी सेवाओं के लिए प्राप्त विदेशी विनिमय; और

(घ) विदेशी व्यापार नीति के अध्याय 9 के दृष्टिकोण से पोर्ट हैंडलिंग सेवाओं के लिए रूपए में प्राप्त भुगतान।

५ (3) "विदेश व्यापार नीति" का अर्थ है समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/2009-2014, दिनांक 27 अगस्त, 2009 के जरिए प्रकाशित विदेश व्यापार नीति 2009-2014;

(5) "लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा क्षेत्रीय प्राधिकारी" का अर्थ है विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक अथवा उक्त अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस अथवा प्राधिकार प्रदान करने के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी;

(6) "उत्पादन" का वही अर्थ है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा (2) के खंड (च) में परिभाषित किया गया है।

(7) "निर्यात उत्कृष्टता वाले शहरों (टी ई ई)" का अर्थ है निर्यात में वृद्धि की क्षमता पर आधारित 750 करोड़ रु. या अधिक के माल का उत्पादन करने वाला चयनित शहर। तथापि हैंडलूम, हस्तशिल्प, कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रारंभिक सीमा 150 करोड़ रु. होगी।

सारणी

क्र.सं.	माल का विवरण
(1)	(2)
1.	सेकेंड हैंड कारखानागत माल सहित उत्पादन पूर्व, उत्पादन और उत्पादन के पश्चात् कारखानागत माल
2.	आयातक द्वारा कारखानागत माल के रूप में एसेम्बल करने के लिए एस केडी/सी केडी में कारखानागत माल शर्त (1) में उल्लिखित ई पी सी जी प्राधिकरण के अंतर्गत
3.	ऐसे आयातित, एसेम्बलड अथवा उत्पादित कारखानागत माल के रख-रखाव के लिए वास्तव में आयातित और अपेक्षित क्रम.सं.1 और 2 में विनिर्दिष्ट माल के सी आई एफ मूल्य के 10% तक के सी आई एफ मूल्य वाले खुले पूर्जें
4.	प्राधिकार धारी के वर्तमान संयंत्र और मशीनरी के बुक वैल्यू के 10% तक सी आई एफ मूल्य वाले खुले पूर्जें

[फा. सं. 605/58/2009-डी बी के]

राजेश कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2009

No. 100/2009-CUSTOMS

G.S.R. 666(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in the Table annexed hereto, from,-

- (i) so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is in excess of the amount calculated at the rate of three percent ad-valorem, and
- (ii) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, when specifically claimed by the importer.

2. The exemption under this notification shall be subject to the following conditions, namely :-

(1) that the goods imported are covered by a valid authorization issued under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme to Common Service Providers(hereinafter referred to as CSP) designated by the Director General Of Foreign Trade (hereinafter referred to as DGFT), Department of Commerce(hereinafter referred to as DOC) or State Industrial Infrastructural Corporation in Towns Of Export Excellence (hereinafter referred to as TEE) in terms of Chapter 5 of the Foreign Trade Policy permitting import of goods at the rate of three percent duty and the said authorization is produced for debit by the proper officer of customs at the time of clearance :

Provided that for import of spare parts specified at Sr.No.4 of the said Table, the validity period of the authorization shall be deemed to be the period permitted for fulfilment of the export obligation in full ;

(2) that the authorization issued under the scheme shall have the details of the users of the said capital goods and the quantum of the Export Obligation(hereinafter referred to as EO) which each user would fulfil.

(3) that the goods imported shall not be disposed of or transferred by sale or lease or any other manner till export obligation is completed.

(4) that the Common Service provider and each of the specific users shall execute a bond in such form and for such sum as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs and a bank guarantee equivalent to their portion of duty foregone in terms of export obligation apportioned in the authorization binding themselves to fulfil export obligation on Free On Board (FOB) basis equivalent to eight times the duty saved on the goods imported as may be specified on the licence or authorization, or for such higher sum as may be fixed or endorsed by the Licensing Authority or Regional Authority in terms of Para 5.10 of the Handbook of Procedures Vol I, issued under para 2.4 of the Foreign Trade Policy, within a period of eight years from the date of issue of licence or authorization, in the following proportions, namely :-

3329 GI/09-3

S.No.	Period from the date of issue of Authorization	Proportion of total export obligation
(1)	(2)	(3)
1.	Block of 1 st to 6 th year	50%
2.	Block of 7 th to 8th year	50%

Provided that where the duty saved is not less than Rupees one hundred crores, or where the authorization is issued to units in the agri export zone as may be notified by the licensing authority or Regional Authority, the export obligation shall be fulfilled within a period of twelve years from the date of issue of authorization in the following proportions, namely :-

S.No.	Period from the date of issue of Authorization	Proportion of total export obligation
(1)	(2)	(3)
1.	Block of 1 st to 10 th year	50%
2.	Block of 11 th to 12th year	50%

Provided further that where a sick unit is notified by the Board for Industrial and Financial Reconstruction(BIFR) or where a rehabilitation scheme is announced by the concerned State Government in respect of sick unit for its revival, the export obligation may be fulfilled within time period allowed by the Licensing Authority or Regional Authority as per the rehabilitation package prepared by the operating agency and approved by BIFR or rehabilitation department of State Government . In cases where the time period is not specified in the rehabilitation package, the export obligation may be fulfilled within the time period allowed by the Licensing Authority or Regional Authority which shall not exceed twelve years.

Provided also that where the capital goods are imported by agro units and units in tiny and cottage sector, the export obligation shall be fixed equivalent to six times the duty saved on the goods imported as may be specified on the authorization, or for such higher sum as may be fixed by the licensing authority, within a period of twelve years from the date of issue of the authorization :

Provided also that where the capital goods are imported for technological upgradation as per conditions specified in Para 5.8 of the Foreign Trade Policy or by small scale industry units as defined in paragraph 5.2 of the Foreign Trade Policy, as the case may be, the export obligation shall be fixed equivalent to six times the duty saved on the goods imported as may be specified on the authorization, or for such higher sum as may be fixed by the Licensing Authority or Regional Authority, within a period of eight years from the date of issue of authorization subject to the further condition that in the case of Small Scale Industry (SSI) units the landed Cost Insurance Freight (CIF) value of such imported capital goods under the scheme shall not exceed Rupees fifty lakhs and total investment in plant and machinery after such imports shall not exceed the SSI limit :

Provided also that spares (including refurbished or reconditioned spares), moulds, dies, jigs, fixtures, tools, refractory for initial lining and catalyst for initial charge, for the existing plant and machinery (imported earlier, under EPCG or otherwise), shall be allowed to be imported under the EPCG scheme subject to an export obligation equivalent to 50% of the normal export obligation prescribed above, to be fulfilled in 8 years reckoned from the date of issue of the Authorization, subject to the condition that the CIF value of import of the said spares etc. will be limited to 10% of the CIF value of the plant and machinery imported under the EPCG authorization or 10% of the book value of the plant and machinery imported earlier otherwise than under EPCG Scheme, as the case may be.

Provided also that export obligation of a particular block may be set off against the excess exports made in the said preceding block(s);

(5) that if the authorisation holder does not claim exemption from the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975, the additional duty so paid by him shall not be taken for computation of the net duty saved for the purpose of fixation of export obligation provided the Cenvat credit of additional duty paid has not been taken;

(6) that the Authorization Holder and the other specific users produce within 30 days from the expiry of each block from the date of issue of authorization or within such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs may allow, evidence to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs showing the extent of export obligation fulfilled, and where the export obligation of any particular block is not fulfilled in terms of the preceding condition, the importer shall within three months from the expiry of the said block pay duties of customs equal to an amount which bears the same proportion to the duties leviable on the goods, but for the exemption contained herein, which the unfulfilled portion of the export obligation bears to the total export obligation, together with interest at the rate of 15% per annum from the date of clearance of the goods;

(7) where the Authorization Holder fulfills 75% or more of the export obligation as specified in condition (4) (over and above 100% of the average export obligation) within half of the period specified for export obligation as mentioned in condition (4), his balance export obligation shall be condoned and he shall be treated to have fulfilled the entire export obligation;

(8) that the capital goods imported, assembled or manufactured are installed in the Common Service Provider's factory or premises and a certificate from the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, is produced confirming installation and use of capital goods in the Common Service Provider's factory or premises, within six months from the date of completion of imports or within such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow :

Provided that in case of import of spares, the installation certificate shall be produced within three years from the date of import :

Provided further that if the Authorization Holder is not registered with central excise or if he is a service provider, as the case may be, he may produce the said certificate of installation and usage issued by an independent Chartered Engineer :

Provided also that agro units located in Agri Export Zones or service providers in Agri export Zones may move the capital goods within the Agri Export Zones under intimation to the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, subject to the condition that the importer shall maintain accurate record of such movement;

(9) that the imports and exports are undertaken through sea ports at Bedi (including Rozi-Jamnagar), Chennai, Cochin, Dahej, Dharamtar, Haldia (Haldia Dock complex of Kolkata port), Kakinada, Kandla, Kolkata, Krishnapatnam, Magdalla, Mangalore, Marmagao, Muldwarka, Mumbai, Mundhra, Nagapattinam, Nhava Sheva, Okha, Paradeep, Pipavav, Porbander, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam and Vadinar or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Chennai, Cochin, Coimbatore, Dabolim (Goa), Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kolkata, Lucknow (Amausi), Mumbai, Nagpur, Rajasansi (Amritsar), Srinagar, Trivandrum and Varanasi or through any of the Inland Container Depots at Agra, Ahmedabad, Anaparthi (Andhra Pradesh), Babarpur, Bangalore, Bhadohi, Bhatinda, Bhilwara, Bhiwadi, Bhusawal, Chheharata (Amritsar), Coimbatore, Dadri, Dappar (Dera Bassi), Daulatabad (Wanjarwadi and Maliwada), Delhi, Dighi (Pune), Durgapur (Export Promotion Industrial Park), Faridabad, Garhi Harsaru, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jalandhar, Jamshedpur, Jodhpur, Kanpur, Karur, Kota, Kundli, Loni (District Ghaziabad), Ludhiana, Madurai, Malanpur, Mandideep (District Raisen), Miraj, Moradabad, Nagpur, Nasik, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Pondicherry, Raipur, Rewari, Rudrapur (Nainital), Salem, Singanalur, Surat, Surajpur, Tirupur, Tuticorin, Udaipur, Vadodara, Varanasi, Waluj (Aurangabad) or through the Land Customs Station at Agartala, Amritsar Rail Cargo, Attari Road, Changrabandha, Dawki, Ghojadanga,

3329 GI/09-4

Hilli, Jogbani, Mahadipur, Nepalganj Road, Nautanva (Sonauli), Petrapole, Ranaghat, Raxaul, Singhabad and Sutarkhandi or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may, by special order or a public notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other sea-port, airport, inland container depot or through a land customs station within his jurisdiction.

(10) notwithstanding anything contained in condition (6) above, where the Licensing Authority or Regional Authority grants extension of block-wise period for any block(s) or overall period of fulfilment of export obligation upto a period of two years or regularization of shortfall in export obligation, not exceeding five percent of such export obligation, the said block-wise period or overall period of export obligation shall be extended or condoned by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be :

Provided that in respect of sick units referred to in the second proviso to condition (4) extension of overall period of export obligation shall not be allowed :

Provided further that the Regional Authority may grant further extension in the overall period of export obligation upto a period of further two years if the authorization holder pays fifty percent of duty payable in proportion to the unfulfilled portion of export obligation and agrees to fulfill other conditions as may be specified by the Regional Authority for this purpose;

Provided further that the Export Obligation period shall not be extended beyond 12 years including the original Export Obligation period of 8 years or 12 years as the case may be.

3. Where the goods specified in the said Table are found defective or unfit for use, the said goods may be re-exported back to the foreign supplier within three years from the date of payment of duty on the importation thereof:

Provided that at the time of re-export, the goods are identified to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, to be the same as the goods which were imported.

Explanation – For the purpose of this notification, -

1. "Capital goods" has the same meaning as assigned to it in Paragraph of 9.12 of the Foreign Trade Policy;

2. Common Service Provider (CSP) means a service provider who is designated or certified as a Common Service Provider by the DGFT, Department of Commerce or State Industrial Infrastructural Corporation in a Town of Export Excellence.

3. "Export obligation", -

(1) means obligation on the Common Service provider and each of the specific users to export to a place outside India, goods manufactured or capable of being manufactured or services rendered by the use of capital goods imported in terms of this notification. The export obligation shall be over and above the average level of exports achieved by the Common Service provider or the specific user in the preceding three licensing years for the same and similar products within the overall export obligation period including the extended period, if any. Such average shall be the arithmetic mean of export performance in the last 3 years for the same and similar products.

Provided that upto 50% of the export obligation may also be fulfilled by export of other good(s) manufactured or service(s) provided by the Common Service provider / the specific user or his group company or managed hotel, which has the EPCG authorization subject to the condition that in such cases, additional export obligation imposed shall be over and above the average exports achieved by the Common Service provider / the specific user or his group company or managed hotel in preceding three years for both the original and the substitute product(s) or service(s) :

Provided further that in case of export of goods relating to handicraft, handlooms, cottage, tiny sector, agriculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry and sericulture, the Common Service provider or the specific user shall not be required to maintain the average level of exports :

Provided further that in case of export of goods relating to aquaculture(including fisheries), the Common Service provider or the specific user shall not be required to maintain the average level of exports subject to the condition that EPCG authorization has been obtained for goods other than fishing trawlers, boats, ships and other similar items.

Provided also that the goods, excepting tools, imported under this notification by the aforesaid sectors, shall not be allowed to be transferred for a period of five years from the date of imports even in cases where export obligation has been fulfilled. Transfer of capital goods would, however, be permitted within the group companies, after fulfilment of export obligation but before five years from the date of imports, under intimation to Regional Authority and jurisdictional Central Excise Authority :

Provided also that exports made to former USSR, or to such countries as notified by Director General of Foreign Trade as on 31.3.08, shall not be counted for fixing the average level of exports :

Provided also that exports against only such shipping bills which mention the EPCG authorization No. and date shall be counted for the discharge of the export obligation;

Provided also that exports counted against the authorization issued under this notification shall not be counted towards fulfilment of other specific Export Obligations against other EPCG authorizations;

(2) shall be fulfilled through physical exports and the export proceeds shall be realized in freely convertible currency. However the following categories of supplies, shall also be counted towards fulfilment of export obligation:

(a) deemed exports, namely:

(i) supply of goods against Advance Authorization/Advance Authorization for Annual Requirement/ Duty Free Import Authorization (DFIA);

(ii) supply of goods to Export Oriented Units (EOUs) or Software Technology Parks (STPs) or Electronics Hardware Technology Parks (EHTPs) or Bio-Technology Parks (BTPs);

(iii) supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies or Funds as notified by Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance (MOF) under International Competitive Bidding (ICB) in accordance with procedures of those agencies or Funds, where legal agreements provide for tender evaluation without including customs duty; supply and installation of goods and equipments (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral agencies or Funds as notified by DEA, MOF under ICB, in accordance with procedures of those agencies/Funds, where bids may have been invited and evaluated on the basis of Delivery Duty Paid (DDP) prices for goods manufactured abroad;

(iv) supply of goods to any project or purpose in respect of which the Ministry of Finance, by a notification, permits import of such goods at zero customs duty and the supply is made under ICB procedure;

(v) supply of goods to power projects and refineries not covered in (iv) above under ICB procedure;

(vi) Supply of goods to nuclear power projects through competitive bidding as opposed to ICB;

(b) Supply of ITA-1 items to Domestic Tariff Area, provided realization is in free foreign exchange;

(c) Royalty payments received in freely convertible currency and foreign exchange received for Research and Development (R and D) services; and

(d) Payments received in rupee terms for port handling services in terms of chapter 9 of the Foreign Trade Policy.

4. "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy 2009-2014 published in the gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, No. 1/2009-2014 dated the 27th August, 2009 as amended from time to time;

5. "Licensing Authority or Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorized by him to grant an authorization under the said Act;

6. "Manufacture" has the same meaning as defined in clause (f) of section 2 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944).

7. "Towns of Export Excellence(TEE)" means a selected town producing goods of Rs.750 Crores or more based on potential for growth in exports. However for TEE in Handloom, Handicraft, Agriculture and fisheries sector the threshold limit would be Rs.150 Crores.

Table

S.No.	Description of goods
(1)	(2)
1.	Capital goods for pre-production, production and post production including second hand capital goods.
2.	Capital goods in Semi Knocked Down (SKD) / Completely Knocked Down (CKD) conditions to be assembled into capital goods by the importer.
3.	Spare parts of CIF value upto 10% of the CIF value of goods specified at Serial Nos.1 and 2 as actually imported and required for maintenance of capital goods so imported, assembled, or manufactured.
4.	Spare parts of CIF value upto 10% of the book value of the existing plant and machinery of the authorization holder.

[F. No. 605/58/2009-DBK]

RAJESH KUMAR AGARWAL, Under Secy.